

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
प्रथम एवं द्वितीय तल, सी0जी0ओ0 परिसर,
लांगवुड, शिमला-171001

वर्तमान पता: एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,
देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, SHIMLA
FIRST & SECOND FLOOR, C.G.O COMPLEX
LONGWOOD, SHIMLA-171001
PRESENT ADDRESS: INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/एच.पी./01/116/2019/एफ.सी. 1108

दिनांक: 22/06/2021

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

विषय: **Diversion of 9.739 ha of forest land in favour of HPSEB Ltd. for the construction of Devi Kothi Hydel Electric Project (16.00 MW), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, H.P. (online no. FP/HP/HYD/32280/2018)**

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश का पत्रांक-एफ0टी0 48-3731/2018 (एफ0सी0ए0), दिनांक 11.02.2021

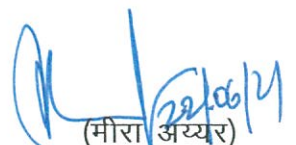
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली भेजा गया था, जहां प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत निम्न कमी पायी गयी है:

1. With regards to the status of implementation of Comprehensive CAT Plan, current status of implementation providing details of area treated and funds utilized, in general and with respect of proposals earlier approved by the Central Government in particulars, as desired by the Ministry has not been provided by the State govt.
2. With regard to information on breaking the proposal of transmission line and hydel (dam) into two separate proposal. The state govt. in their reply adverted to the submission of the User Agency and forwarded the same to the IRO. Comments of State Govt. is required in this regard alongwith details of projects for which T/L will jointly be constructed.
3. Revised cost benefit analysis as per the relevant guidelines given in the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 has been submitted. CB ration has been reported to be 1:259.06 which is high. Comments in this regard is required to be submitted.

अतः राज्य सरकार उक्त कमी हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीया,


(मीरा अग्रवाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

for cds record folder